

प्रत्येक राजकीय भवन की होगी जओ-टैगिंग

चर्चा में क्यों?

18 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के विभिन्न विभागों व उपकरणों की परसिंपत्तियों, योजनाओं एवं कार्यों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के माध्यम से जओ-टैगिंग कर उन्हें मैप से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस हेतु प्रारंभ में 153.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से अब राज्यव्यापी जीआईएस प्रणाली के माध्यम से सभी विभाग अपनी परसिंपत्तियों, सुविधाओं, योजनाओं व कार्यक्रमों का भू-स्थानिक डाटा जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म से जोड़ सकेंगे। इससे संसाधन संग्रहण एवं वितरण, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के नीति नियोजन के संबंध में नरिणय लेने और उनके नरीक्षण में आसानी होगी।
- उक्त नरिणय से विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के भू-चहिनति सर्वेक्षण से कषेत्रीय स्तर पर सेवा प्रदायगी बेहतर हो सकेगी। आपदा या महामारी के दौरान संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी इस प्रणाली के माध्यम से हो सकेगा। साथ ही, राज्य के सभी राजकीय भवन एक ही मैप पर उपलब्ध होंगे तथा आमजन के लिये इन भवनों तक पहुँचना आसान हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि जओ-टैगिंग के अंतरगत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। विभिन्न विभागों, जैसे- महिला एवं बाल विकास विभाग, पीएचईडी, भू-जल विभाग, चकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आदिद्वारा ऐप का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।
- जीआईएस एक ऐसी प्रणाली है, जिसि पृथ्वी की सतह पर भौगोलिक स्थतियों के संबंध में डाटा एकत्रित करने, संग्रहति करने, संशोधन करने तथा वश्लेषण करने के लिये बनाया गया है। साथ ही, इस प्रणाली से डाटा प्रबंधति करने तथा प्रस्तुत करने का कार्य भी किया जा सकता है।